

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर ।

अपील संख्या - 1027/2016

काबू पुत्र श्री धन्ना जाति मीणा, निवासी कांकरेल, तहसील
आमेर, जिला जयपुर । - अपीलार्थी

बनाम

1. भगवानसहाय पुत्र श्री गंगाराम, जाति मीणा, निवासी
ग्राम कांकरेल, तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल निवासी
प्लॉट संख्या 6, गंगाविहार, जगतपुरा, जयपुर ।
2. सरकार जिरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जयपुर ।
3. श्रीमती कमलादेवी पत्नी श्री कल्याण सहाय मीणा,
निवासी ग्राम कांकरेल, तहसील आमेर, जयपुर ।
- रेस्पोंडेन्ट्स

उपस्थित अधिवक्तागण :-

1. श्री मुकेश शर्मा अपीलार्थी की ओर से ।
2. रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

- : निर्णय :- दिनांक 08.03.2018

- 1- यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान क्रांतिकारी
अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 23-
11-2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर प्रस्तुत की
गई है ।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी
वादी द्वारा अधिनियम न्यायालय के समक्ष एव वह
अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 राजस्थान क्रांति-
कारी अधिनियम वाकत घोषणा, इन्ड्रोज दुखस्ती, विमा-
जन एवम् स्मार्ड निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। वादी
द्वारा वाद में कथन किया गया कि आराजी सावित्रा
खसरा नम्बर 371 रकबा 28 बीघा 06 बिश्वा वाके ग्राम
कांकरेल पूर्व में गंगाराम पुत्र नानगा की खातेदारी भूमि
थी जिसे वादी द्वारा जिरिये संक्षिप्त विषय विलेख



दिनांक 08.08.1984 को क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त कर लिया गया तथा उक्त विडय पत्र के आधार पर वादी के पक्ष में नामान्तरकरण दिनांक 02.09.1984 को तसदीक होकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर दिया गया। भूप्रबन्ध कार्यवाही में उक्त साबिक खसरा नम्बर 371 के नये खसरा नम्बर 1786 कायम कर रकका 0.58 हेक्टेयर दर्ज कर दिया गया। उक्त भूमि में से 0.29 हेक्टेयर साराजी का बेचान वादी द्वारा दिनांक 29.07.04 को सोनी देवी धर्मपत्नी प्रभात मीणा को जरिये विडय पत्र कर दिया गया तथा सोनी देवी ने प्रतिवादी संख्या 01 भगवान सहाय को विडय कर दिये जाने से बाद-गुस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 01 की $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ हिस्से की खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 01 0.29 हेक्टेयर भूमि पर तथा शेष भूमि पर वादी काबिज कायत है। वादी की खातेदारी भूमि रकका 03 बीघा 06 बिश्वा मेट्रिक प्रणाली में 0.83 हेक्टेयर होती है परन्तु भूप्रबन्ध विभाग द्वारा इसे 0.58 हेक्टेयर दर्ज कर दिया गया। मानचित्र नापने से उक्त भूमि 0.73 हेक्टेयर होती है तथा इसी अनुसार मौके पर कब्जा है। वादी द्वारा कथन किया गया कि जमाबन्दी एवम् मानचित्र में अन्तर नहीं हो, इसलिए जमाबन्दी में रकका दुरुस्ती की जाकर ख.न. 1786 का रकका 0.73 हेक्टेयर दर्ज किये जाने तथा इसमें से वादी का हिस्सा $\frac{44}{73}$ व प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा $\frac{29}{73}$ दर्ज किये जाने का वादी जबाबदारी है तथा बाद दुरुस्ती रिकॉर्ड भूमि का विधिवत विभाजन किये जाने का जबाबदारी है। उक्त आशय का बाद प्रस्तुत कर वादी द्वारा घोषणा, इन्फॉर्म दुरुस्ती, तकासमा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। दौराने बाद प्रतिवादी संख्या 01



राजस्व अपील अधिकारी
जलंधर

द्वारा अपने हिस्से की भूमि श्रीमती कमला देवी पत्नी कल्याण सहाय को विक्रय कर दिये जाने से श्रीमती कमला देवी को कर्तोर पक्षकार प्रतिवादी संख्या 03 संयोजित किया गया। अखिल न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय व डिडी दिनांक 23.11.2016 पारित किया जाकर वादी का वाद खारिज फरमा दिया गया। उक्त निर्णय व डिडी के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3- अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील मीमो में वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा आधार लिये गये कि अपीलाधीन निर्णय व डिडी विविध प्रावधानों एवम् तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। वादी का वाद प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड से ब्यूरी सिद्ध होता है परन्तु न्यायालय द्वारा दस्तावेजात व तथ्यों का न्यायिक विश्लेषण नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त कथन कर अपीलाधीन निर्णय व डिडी दिनांक 23.11.2016 निरस्त किये जाने एवम् वादी का वाद डिडी किये जाने का अनुतोष -वाहा गया।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। आवजूह तमील रेस्पोंडेन्ट्स की क्षेय से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अखिल न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस अविवक्ता अपीलार्थी सुनी गई।

5. अविवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा कथन किया गया कि अखिल न्यायालय द्वारा बिना न्यायिक विश्लेषण का उपयोग किये तथा दस्तावेजों



का अवलोकन किये पारित किया गया है। वादी का वाद तहसीलदार की रिपोर्ट से भी ख़ूबकी साबित था परन्तु विद्वान न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर वादी का वाद खारिज फरमा दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार की जाकर वाद डिफ़ी फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

6. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवम् बहस में किये गये कथन पर मनन किया गया। अखिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवम् उसपर उपलब्ध दस्तावेज़ात का अवलोकन किया गया। अखिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। विद्वान न्यायालय द्वारा तहसीलदार ज़ामेर से मौवा व रिकॉर्ड की जांच की जाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई है। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.09.2015 में दल्लेख किया गया है कि:-

“ 1. आरानी ख. न. साबिक 371 रकबा 03 कीचा 06

बिश्वा ग्राम कांकरेल में गंगाराम S/O नानगा की कब्जे व खातेदारी में दर्ज थी। गंगाराम ने उक्त ख. न. का खेचान वादी को दिनांक 08.08.84 कर कब्जा संभला दिया था।

2. यह है कि उक्त विषय पत्र का नामान्तकरण दिनांक 2-9-1984 तसदीक होकर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज हो गई थी।

3. यह कि सेटलमेंट सार्यवाही में उक्त ख. न. साबिक 371 के हाल ख. न. 1786 रकबा 0.58 हे. दर्ज हो गया है।

4. यह कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में ख. न. 1786 रकबा 0.58 हे. है लेकिन राजस्व नक़्शे में रकबा 0.73 हे. के लगभग है।

5. यह कि ख. न. 1786 का उपयोग कृषि कार्य में हो रहा है।”



राजस्व अपील अधिकारी
ज्योती

किया गया है। पूर्व खातेदार द्वारा तसदीक कराये गये विवरण पत्र तथा नामान्तरकरण सं २४ सेंटनर प्रविष्टियों से स्पष्ट है कि साबिक ख. न. २७/८ रकबा २ बीघा ६ बिस्वा था। तहसीलदार द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में इसे सही माना है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन दस्तावेजी साक्ष्यों की अनदेखी कर भू-उपन्य की कार्यवाही को अनुमान के आधार पर सही माना गया है जबकि वादी द्वारा अपना वाद ही भू-उपन्य विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवम् मौखिक साक्ष्य तथा तहसीलदार की रिपोर्ट से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पुष्ट होता है तथा प्रतिवादीगण द्वारा अस्वीकृति का कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलार्थी निर्णय व डिप्री यथावत रखे जाने योग्य नहीं है तथा वादी/अपीलार्थी का वाद बाधत घोषणा डिप्री बिये जाने योग्य है।

7. अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलार्थी निर्णय व डिप्री दिनांक 23.11.2016 निरस्त किये जाते हैं तथा ख. न. 1786 का रकबा 0.58 हैक्टेयर के स्थान पर 0.73 हैक्टेयर दुरुस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। एवम् ख. न. 1786 के रकबा 0.73 हैक्टेयर में वादी को 44/73 हिस्से तथा प्रतिवादी सं० 2 को 29/73 हिस्से का खातेदार दाशतकार घोषित किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिप्री जारी किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि नियमानुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन के वाद का निस्तारण किया जावे। पत्रावली केसल शुमार होकर नम्बर

से कम हो।

8. निर्णय आज दिनांक 08.03.2018 को सुनाया
गया।



वाजस्व अपील प्राधिकारी,
जयपुर।